



शहरी विकास मंत्रालय ने एनसीआरपीबी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के निष्पादन में देरी को गंभीरता से लिया
देरी के कारण दिल्ली में कड़कड़ूमा बहु-मंजिला कार्यालय परिसर के लिए लोन को रद्द
किए जाने की सीधी समीक्षा

हरियाणा से नई परियोजनाओं पर विचार किए जाने से पहले एडीबी द्वारा वित्तपोषित
सड़क परियोजनाओं संबंधी मुद्दों का समाधान करने के लिए कहा गया

राजस्थान को जयपुर में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 1,664 करोड़ रुपये की
कर्ज सहायता मिली

पिंक सिटी को साइक्लिंग और वाकिंग की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए कहा गया

Posted On: 27 JAN 2017 8:17PM by PIB Delhi

शहरी विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं, जिनके लिए एनसीआर योजना बोर्ड ने वित्तीय सहायता भी बढ़ाई थी, के निष्पादन में देरी को गंभीरता से लिया है। सचिव (शहरी विकास) श्री राजीव गोबा ने यह संदेश सदस्य राज्यों को देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अब कर्ज सहायता परियोजनाओं की प्रगति को ध्यान में रखकर दी जाएगी।

परियोजना मंजूरी और निगरानी समूह की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री गोबा ने पूर्वी दिल्ली के कड़कड़ूमा इंस्टीट्यूशनल इलाके में बहु-मंजिला कार्यालय इमारत के निर्माण के लिए वर्ष 2013 में लोन की 20 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी किए जाने के बाद परियोजना में देरी के चलते मंजूर किए गए 100 करोड़ रुपये के कर्ज को रद्द करने के लिए उसकी समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं।

हरियाणा सरकार से भी कहा गया कि पहले के लंबित एडीबी वित्तपोषित सड़क परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों के समाधान के बाद ही विभिन्न बुनियादी परियोजनाओं के लिए एनसीआरपीबी द्वारा सहायता किए जाने पर विचार किया जाएगा।

परियोजना मंजूरी और निगरानी समूह ने हरियाणा सरकार को सूचित किया है कि अगर जल्द से जल्द कार्य शुरू न हुआ तो 223 करोड़ की मानेसर जल आपूर्ति परियोजना के लिए मंजूर किए गए 168 करोड़ रुपये के कर्ज की भी समीक्षा की जाएगी। इस परियोजना के लिए मंजूर लोन की 31.13 करोड़ रुपये की पहली किस्त पिछले वर्ष मार्च में जारी कर दी गई थी लेकिन हरियाणा राज्य औद्योगिक बुनियादी ढांचा विकास निगम ने अभी तक किसी तरह की कोई प्रगति रिपोर्ट नहीं सौंपी है। समूह ने मुंडका से बहादुरगढ़ के मेट्रो लिंक के लिए हरियाणा मेट्रो रेल परिवहन निगम द्वारा की गई 270 करोड़ रुपये के लोन की मांग को भी यह कहते हुए ठुकरा दिया है कि यह मूल वित्तपोषण योजना के अनुरूप नहीं है।

एनसीआर योजना बोर्ड के परियोजना मंजूरी और निगरानी समूह ने आज कुल 2,377 करोड़ रुपये की लागत वाली विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए 1,664 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता को मंजूरी दे दी है।

वीके/पीवी/सीएस - 269

(Release ID: 1481301) Visitor Counter : 9

